



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, ३१ मार्च, १९९५/१० चैत्र, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २१ मार्च, १९९५

संख्या आयु०-छ(४)-३/९३.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित स्थानों पर जनहित में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के तत्काल से सहर्ष आदेश देते हैं :—

जिला का नाम १	चुनाव क्षेत्र का नाम २	औषधालय का नाम ३
बिलासपुर	धुमारवीं बिलासपुर कोट महलूर गेहडवीं	बम वाड़ी भगोट नंगेठाकुर घरान

1	2	3
चम्बा	भरमौर भटियात बमीयेत  चम्बा	गराहन भरिया कोठी हिमागरी कोठी (अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है) । बामनी
कांगड़ा	जाहपुर मगरौठा यतबां मंगध नुरपुर जसबां गुलेर बैजनाथ धुरल राजगीर कवाली कांगड़ा पालमपुर परागपुर ज्वालामुखी सूतह धर्मशाला	पलबाला समुच्चयों सूरुवां अतरोली गुलारघार लुधियार बही संधोल दगोह सुनेत ढगवार खलेट मनयाला देहरिया काहनपट गगल
किन्नीर	किन्नीर	रामनी
कुल्लू	कुल्लू बन्जार आर्मी	वाशिष्ट जंष्टा रावा
लाहौल स्थिति	लाहौल स्थिति	खुरिक
शिमला	शिमला चीपाल रामपुर जुब्बल-कोटबाई रोहड़  कुमारसेन कसुम्पटी ठियोग	चम्कर खगना ब्योट (ठारु) सालना जिमकून (अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है) । बन्हार व्यूनिषा कमाह

1	2	3
मण्डी	धर्मपुर नाचन बच्चोट श्रंग कर्मसोग मण्डी जोगिन्द्रनगर गोपालपुर बल्ह सुन्दरनगर	गरी छानर गत् गुडमा संसगत पधिवं बारी स्तिवा नागबला पुरना बाजार सुन्दरनगर
सोनम	शर्की यसोली सोनम नाम्नागढ़ दून	अगल नडोग ग्राम कोठी सफेदी लौदी माजरा
सिरमोर	रेणुहा पावटा सहिन फिनाई पच्छाद नाहन	सताहन पिलोडी बेणवा कल्याण बन हला
हमीरपुर	मेवा बगसल नदौनवा हमीरपुर नदौन	भुक्कड बनलन जजरी ब्याह मलू
ऊना	ऊना गगरेट चिन्तपुरणी कुटलीठंड सन्तोखगढ़	रायपुर सहोड़ा भंमाल ठाठम नाहरी देवी सिंह पालाहवाह

प्रादेशी द्वारा,

जे 0 पी 0 नेमी,

प्रायुक्त एवं सचिव ।

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-171002, 27 मार्च, 1995

संख्या एच० एफ० डी०बी० (एफ०) 4-13/94.—राज्यपाल हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित स्थानों पर जनहित में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सहर्ष आदेश देते हैं:—

स्थान का नाम 1	जिला 2
1. मलांगन	बिलासपुर
2. तरहड़	"
3. सलोह	"
4. जातकारी	चम्बा
5. अमरोह	हमीरपुर
6. धरोग	"
7. जमली तहसील भोरंज	"
8. मेयर (पलमी)	"
9. भीऊ	"
10. महोली ग्राम पंचायत समलेत	कांगड़ा
11. कुठियाड़ा	"
12. अमरोहनंद मलांड	"
13. वहलाड़	"
14. घाड़न	"
15. भुगनाग	"
16. मुधेड़	"
17. थारी, ग्राम पंचायत दाडी	"
18. अलोड, कांगड़ा	"
19. जन्दराह	"
20. राख ग्राम पंचायत	"
21. चाम्बा	"
22. खजरनू	"
23. बृहत	"
24. शिल नाला	कुल्लू
25. देवहोी ग्राम पंचायत कांगू	मण्डी
26. दांगी	"
27. मुलपुर बही	"
28. धवाली, ग्राम पंचायत धवाली	"
29. थमाडी, ग्राम पंचायत रोहाण्डा	"
30. पीपली	"
31. हार्ट, ग्राम पंचायत कांठली	"
32. जौल, ग्राम पंचायत बल्ह	"
33. गांव कोठी	शिमला
34. थोगर, ग्राम पंचायत किरण	"



1

2

35. डोमेहर तहसील मुन्नी	शिमला
36. केल्ही	"
37. अन्नाडेल	"
38. चनोग, ग्राम पंचायत चनोग	"
39. शाडीया	सिरमौर
40. पीपलीघाट ग्राम पंचायत मेना	"
41. मानपुर देवडा	"
42. शिल्ली, ग्राम पंचायत सलोगड़ा	सालन
43. गुलाड़ी	"
44. कुन्गाहल	"
45. कांगन बाल, ग्राम डांग	"
46. नगल सलोगड़ी	ऊना
47. जनानी पोलियां बीट	"
48. डंगगोली	"
49. चौवार	"

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,  
आयुक्त एवं सचिव ।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 मार्च, 1995

संख्या शिक्षा-सी०-म० (1)-9/93.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 6-III-म(1) 23/90, दिनांक 6-12-1990 का अधिकरण करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर खरीदने के लिए निम्नलिखित उच्च स्तरीय क्रय समिति का गठन करते हैं :—

1. अतिरिक्त सचिव शिक्षा	अध्यक्ष
2. निदेशक उच्च शिक्षा	सदस्य
3. निदेशक प्राथमिक शिक्षा	सदस्य
4. प्रबन्ध निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स निगम या प्रतिनिधि	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (वित्त)	सदस्य
6. भण्डार खरीद नियन्त्रक या प्रतिनिधि	सदस्य
7. शिक्षा विभाग के सम्बन्धित संयुक्त/उप-निदेशक	सदस्य-सचिव ।

कमेटी का कार्य निम्न प्रकार होगा :

1. हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में स्कूलों हेतु रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए उपलब्ध करवाने तथा उनकी खरीद का निर्णय लेना ।

2. इस मद्द पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों व सरकार द्वारा दर ठेका (Rate contract) भी ध्यान में रखा जाए।

आदेश द्वारा, १६

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।

## FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 15th March, 1995*

No. FDS.B(1)/94.—The Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all earlier notifications issued in this behalf, in exercise of the powers vested in him under section 9 & 10 of the Consumer Protection Act, 1936, hereby establishes a Consumer Disputes Redressal Forum to be known as the District Forums Shimla for the Revenue District of Shimla, Sirmaur, Solan and Kinnaur with its headquarters at Shimla with immediate effect.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the District Forum Shimla shall consist of :—

- (a) a President who is, or who has been, or is qualified to be a District Judge; and
- (b) two other members to be appointed on part-time basis who shall be persons of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge or experience of, or have shown capacity in dealing with, problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration, one of whom shall be a woman.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to direct that the District Forums functioning at present in the Districts of Shimla, Sirmaur, Solan and Kinnaur shall cease to function w. e. f. the date of issue of this notification.

By order,

P. S. NEGI,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

### CORRIGENDUM

*Shimla-2, the 28th March, 1995*

No. FDS. B (1) 1/94.—Please add the word after the word "District Forum" "Kangra at" before the word Dharamshala appearing at the end of the fifth line of this Department Notification of even number dated the 15th March, 1995.

Sd/-  
Under Secretary.

[Authoritative English text of this Department Notification No. VAN (A) 4-3/91-Vol. III dated 10th March, 1995 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FOREST FARMING AND CONSERVATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 10th March, 1995*

No. VAN (A) 4-3/91-Vol. II.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of section 8 of the Himachal Pradesh Kutehar Forest (Acquisition of Management) Act, 1992 (Act No. 19 of 1992), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Divisional Commissioner, Kangra Division, Dharamshala to decide the question, as and when it arises, as to whether any person was a whole time employee in or in connection with the management of the Kutehar Forest immediately before the appointed day and has become an employee of the Government under sub-section (1) of section 8 of the said Act.

By order,  
Sd/-

*Financial Commissioner-cum-Secretary.*

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

*Shimla-2, the 1st March, 1995*

No. GAD-7 (G) 1-7/84 (Loose).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that in supersession of notification No. 6-59/82-ID (Sectt.), dated 4-2-1983, Himachal Bhawan, New Delhi will be run under the supervision and control of the Managing Director, H. P. Tourism Development Corporation Ltd. w. e. f. 1-4-1995 on the following terms and conditions:—

1. Himachal Bhawan, New Delhi will be run as a State Guest House and as a distinct entity with its own accounts/account books and assets and liabilities/income and expenditure. All such assets and liabilities/income and expenditure will be of Himachal Pradesh Government.
2. Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd. will deploy Managers/Staff etc. may be required. Such staff will get the same pay and other benefits had they been posted in a HPTDC Unit.
3. The rates of accommodation, auditorium, conference hall charges etc. and also of food and other services will be fixed by the Government. Reservation will also continue to be controlled by the State Government in the General Administration Department.
4. In case of any difference between income and expenditure of Himachal Bhawan, New Delhi, the difference if surplus will be deposited by Himachal Bhawan, New Delhi in the Government treasury. In case the difference is a deficit, Government will release funds in four quarterly instalments on the basis of deficit of the previous year and the balance, if any, will be made up in the first month of the next financial year.

5. The Managing Director, HPTDC will have the same financial and administrative powers in respect of Himachal Bhawan, New Delhi as are exercised by him in HPTDC/its units.
6. The accounts of Himachal Bhawan, New Delhi will be audited by the auditors appointed by HPTDC.
7. The General Administration Department of the State Government will be the Administrative Department for Himachal Bhawan, New Delhi.
8. All necessary repairs and maintenances, additions and alterations, improvements etc. of Himachal Bhawan, New Delhi will be carried out by HPTDC and not by the Public Works Department.
9. This issues with the prior concurrence of Finance Department vide their Diary No. 545-Fin (F)/95, dated 22-2-1995.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

शिमला-2, 25 मार्च, 1995

संख्या जी० ए० वी० (जी० आई०) 6 (एफ) 12/77.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा में विद्यमान उप-तहसील फतेहपुर का दर्जा, उन्हीं सीमाओं और अधिकांशता सहित जो विद्यमान उप-तहसील फतेहपुर की हैं, बढ़ा कर उसे पूर्ण तहसील बनाए जाने के लिए तत्काल आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

आर० के० आनन्द,  
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification No. GAB (GI) 6 (F) 12/77, dated 25-3-1995 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

Shimla-2, the 25th March, 1995

No. GAB (GI) 6 (F) 12/77.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the upgradation of the existing Sub Tehsil, Fatehpur, District Kangra to that of a Full-fledged Tehsil, with the same boundaries and jurisdiction as that of the existing Sub-Tehsil, Fatehpur, with immediate effect.

By order,

R. K. ANAND,  
Chief Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मार्च, 1995

संख्या गृह(सी)एफ(6)-1/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 21(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से और उपरोक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन गठित समिति की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन करते हैं, जिसके निम्नलिखित अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे अर्थात् :—

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बाला कृष्णा मेनन,<br>लोकायुक्ता, हिमाचल प्रदेश।               | अध्यक्ष         |
| 2. माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री रूप सिंह ठाकुर<br>उपाध्यक्ष, पर्यावरण संरक्षण, हिमाचल प्रदेश। | सदस्य           |
| 3. माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री व्योम प्रकाश  | सदस्य           |
| 4. डा० एच० पी० दीक्षित,<br>उपकुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय।                                      | सदस्य           |
| 5. श्री टी० एन० वैद्य,<br>सचिव, विधिक सहायता बोर्ड, हिमाचल प्रदेश।                                     | सदस्य           |
| 6. लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश का सचिव   | सदस्य-<br>सचिव। |

उपरोक्त आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा।

[Authorised English text of this department notification No. HOM(C)F(6)-1/94, dated 18-3-95 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

Shimla-2, the 18th March, 1995

No. HOM(C)F(6)-1/94.—In exercise of the powers conferred under section 21(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No. 10 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court and on the recommendations of the Committee constituted under first proviso of Sub-Section (1) of Section 22 of the Act is pleased to constitute the Himachal Pradesh Human Rights Commission with the following as Chairperson and other members, namely:—

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Hon'ble Justice (Retd.) Mr. Balakrishna Menon,<br>Lokayukta, Himachal Pradesh.                             | Chairperson |
| 2. Hon'ble Justice (Retd.) Mr. Roop Singh Thakur,<br>Vice-Chairman, Environment Protection, Himachal Pradesh. | Member      |

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 3. Hon'ble Justice (Retd.) Mr. Vyom Prakash                           | Member            |
| 4. Dr. H. P. Dixit,<br>Vice-Chancellor, H. P. University.             | Member            |
| 5. Mr. T. N. Vaidya,<br>Secretary, Legal Aid Board, Himachal Pradesh. | Member            |
| 6. Secretary to Lokayukta, Himachal Pradesh                           | Member-Secretary. |
2. The aforesaid Commission shall have its headquarters at Shimla.

By order,

S. N. VERMA,  
Commissioner-cum-Secretary.

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

*Shimla-2, the 27th March, 1995*

No. PBW (B & R) (B) 3 (1) 153/94.—Whereas Shri R. L. Sharma, District & Sessions Judge (Retd.) was appointed as a Commission of Inquiry vide this Department Notification of even No. dated 7th December, 1995 to enquire into as to whether the Leo & Powari Bridges were constructed as per specifications & whether the quality of material used was proper.

And, whereas the Commission of Inquiry was required to submit his enquiry report within three months, but for certain reasons he has not been able to submit his enquiry report within stipulated time.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to allow Shri R. L. Sharma to submit his enquiry report by 30th June, 1995 positively.

By order,

R. K. ANAND,  
Chief Secretary.

*Shimla-2, the 27th March, 1995*

No. PBW (B & R) (B) 3 (6) 12/90.—In supersession of this Department notification No. PBW (B) 3 (4)-1/84 dated 5/8th October, 1984, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to rename/declare Parwanoo-Barotiwala-Naina Devi Ji-Bhakra-Una road as State Highways No. 42 with immediate effect.

By order,

P. S. RANA,  
Commissioner-cum-Secretary

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 मार्च, 1995

संख्या पी०सी०एच०एच०एच०(३)-5/94.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी, 1995 के अन्तर्गत जिला कांगड़ा, विकास खण्ड देहरा की ग्राम सभा "बखड़ी (सिलह)" का नाम बदल कर "सिलह" रखने एवं ग्राम सभा के मुख्यालय को स्थान "सिलह" में निर्धारित किये जाने हेतु ग्राम सभा बखड़ी (सिलह) के समस्त सभा सदस्यों से आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं;

और क्योंकि उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों की अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में विभाग में कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) (ग) (घ) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड देहरा की ग्राम सभा "बखड़ी (सिलह)" का नाम बदल कर "सिलह" रखने एवं ग्राम सभा के मुख्यालय को स्थान "सिलह" में निर्धारित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 मार्च, 1995

संख्या पी०सी०एच०एच०एच०(5) 79/92.—यतः अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा श्री बाबू राम, प्रधान, ग्राम पंचायत खाबल, विकास खण्ड चड़गांव, जिला शिमला को समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-94 के अन्तर्गत उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 301, 34 के अन्तर्गत थाना रोहड़ू में अभियोग संख्या 129/94, दिनांक 30-4-94 को गिरफ्तार करके 12-6-94 तक न्यायिक हिरासत में रहने के फलस्वरूप प्रधान पद से निलम्बित किया है;

और यह कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, शिमला से प्राप्त प्रारम्भिक छानबीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात तथा मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा जारी निलम्बन की विनिश्चित अवधि के भीतर-भीतर पुष्टि करना अनिवार्य रूप से उचित समझा गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(3) के अन्तर्गत निहित हैं, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा जारी निम्न आदेश संख्या पी०सी०एच०एच०एच०(5) 79/92, दिनांक 22-11-94 को पुष्टि करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह आदेश दिनांक 20-2-92 से प्रभावी होगा।

शिमला-171002, 20 मार्च 1995

संख्या पी०सी०एच०एच०एच०(5) 253/77.—यतः श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत घरेडो, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला की उप-सम्भागीय अधिकारी (ना०) द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न आरोपों में संलिप्त पाये जाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968

की धारा 57 (जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये) के अन्तर्गत इस कार्यवाही के समन्वयक आदेश दिनांक 4-3-94 द्वारा निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

यह कि उक्त श्री फकीर चन्द ने पंचायत की मु० 11568.75 रु० की धनराशि 23-7-86 से अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी तथा पंचायत निधि में जमा न करवाकर उसका दुरुपयोग किया।

और यह कि ग्राम पंचायत ने उक्त श्री फकीर चन्द को ए० रसीद बुक 0601 से 0700 दिनांक 23-4-86 को जारी की थी परन्तु उक्त रसीद बुक के द्वारा दान सहायक एकत्रित राशि का हिताब पंचायत में न देकर एकत्रित राशि का दुरुपयोग किया।

यह कि उक्त श्री फकीर चन्द ने प्राथमिक पाठशाला भरेड़ी तथा बटीन के निर्माण कार्य हेतु मु० 5665.40 रु० का अनाज प्राप्त किया जिसका हिताब-किताब न देकर राशि का दुरुपयोग किया।

और यह कि कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में उक्त श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेड़ी का जो उत्तर प्राप्त हुआ, पर विचार किया गया जो निम्न कारणों से असन्तोषजनक पाया गया:—

1. यह कि उक्त श्री फकीर चन्द प्रधान ने आरोप नं० 1 मु० 11568.75 रु० की राशि का अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के सन्दर्भ में स्पष्ट किया कि उसने मु० 12000 रु० कंटीन स्कूल हेतु टीन की चादरें क्रय की परन्तु पंचायत रोकड़ में उक्त व्यय का कोई इन्द्राज नहीं पाया गया।
2. यह कि आरोप नं० 2 के सन्दर्भ में उक्त श्री फकीर चन्द का यह कहना है कि उसने कथित रसीद बुक पर कोई राशि एकत्रित न की न जांच के समय उक्त रसीद बुक जांच अधिकारी को सौंपी। वास्तव में पंचायत द्वारा रसीद बुक नं० 0601 से 0700 तक जारी की गई जब कि श्री फकीर चन्द ने जांच अधिकारी को रसीद बुक 601 से 700 तक सौंपी, जिससे स्पष्ट है कि जो रसीद बुक पंचायत ने जारी की थी के बदले नई रसीद बुक मुद्रित करवाना अपराध है और वह भी सम्भावना है कि मूल रसीद के द्वारा एकत्रित राशि का दुरुपयोग किया गया।
3. आरोप नं० 3 के सम्बन्ध में जिसमें मु० 5665.40 रु० के अनाज के दुरुपयोग का आरोप था के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त अनाज का दुरुपयोग किया गया है।

और यह कि उक्त श्री फकीर चन्द ने सभा निधि का दुर्निवर्तन/ छलहरण किया है, जिसके लिए वह अनाचार के दोषी है, ऐसे व्यक्ति का प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर बन रहना जनहित में उचित नहीं समझा गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 148 (1) (ख) व उप-धारा (2) के अधीन निहित हैं, का प्रयोग करते हुए श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेड़ी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला को प्रधान पद से तुरन्त हटाने के अर्थ आदेश देने हैं और यह भी आदेश देते हैं कि वह तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है और छः वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित हो जाएगा।



शिमला-171002, 23 मार्च, 1995

संख्या पी० सी० एच० एच० ए० (5) 38/91.--यतः श्री बाबू राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नम्होल, विकास खण्ड सदर बिलासपुर को उपायुक्त बिनासपुर के माध्यम से उप-सम्भागीय अधिकारी (ना०), सदर बिलासपुर से छानबीन करवाने पर पंचायत निधि व सरकारी धन के दुरुपयोग/छलहरण के निम्न आरोपों में संलिप्त पाए जाने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत निजम्बित किया गया है:—

1. यह कि डंगा निर्माण पंचायत घर नम्होल हेतु "विकास में जनसहयोग योजना" के अन्तर्गत मु० 20,000/- रुपये स्वीकृत किए जिसमें 15,400/- रुपये सहकारी ब 6600/- रुपये जनसहयोग था। श्री बाबू राम प्रधान ने इस कार्य निर्माण हेतु मु० 5,000/- रुपये लोक निर्माण विभाग को पंचायत निधि से दिए साथ ही 20-7-93 से 20-8-93 के मस्ट्रोल के अनुसार 4278/- रुपये का खर्चा पंचायत में भी दर्ज किया, जबकि कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने ही वह डंगा निर्मित किया है, पंचायत ने कोई कार्य नहीं किया है जिसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ने माना है, इस प्रकार श्री बाबू राम प्रधान ने पंचायत द्वारा दर्शाए गए खर्च का दुरुपयोग/छलहरण किया है।
2. यह कि पेयजल टैंक सोसन के निर्माण हेतु विकास में जनसहयोग योजना के अन्तर्गत मु० 4000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई। मौफा पर पाया गया कि श्री बाबू राम प्रधान ने उस राशि से अपनी जमीन में एक टैंक का निर्माण करके उसे निजी प्रयोग में लाया है। स्थानीय जनता के अनुसार उन्हें टैंक के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का कोई ज्ञान नहीं, न ही निमित्त टैंक से उन्हें कोई पानी मिलता है।
3. यह कि सहायक भ-संरक्षण अधिकारी घुमारवीं के रिकार्ड के अनुसार श्री बाबू राम प्रधान को मु० 8000/- रुपये इसी टैंक के निर्माण हेत दिए पाए गए हैं।

और यह कि उपरोक्त वर्णित आरोपों के तथ्यों की वास्तविकता जानने व मामले में पूरी स्थिति सामने लाने के लिए नियमित जांच करवाने का जवाब में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अधीन प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए, श्री बाबू राम, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत नम्होल, विकास खण्ड सदर, जिला बिनासपुर के विरुद्ध आरोपों की सत्यता जानने के लिए अतिरिक्त जिजा दण्डाधिकारी, बिनासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं, साथ ही जिजा अंशेक्षण अधिकारी बिनासपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि पंचायत के अभिलेख के साथ जांच अधिकारी के सनक्ष सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

कुवि उत्सादन आगुवन एवं सचिव।

## समाज एवं महिला कल्याण विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 25 मार्च, 1995

संख्या कल्याण ई0 (3)-3/91-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, बाल आश्रम टुटोमण्डी एवं बालिका आश्रम मशोबरा को राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार के कल्याण विभाग को सौंपने का जनहित में तुरन्त सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।

## TOURISM DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th January, 1995

No. 3-76/86-TSM (SECTT).—In continuation of this Department Notification No.TSM-F (6) 1/93, dated 26-7-1993, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare "Himachal Pradesh Paying Guest House Scheme, 1995" operative with immediate effect as under :—

1. *Object of the Scheme :*

The Scheme aims at augmenting accommodation in the State without disturbing the fragile ecology of the State. It will encourage the local people to participate in the Tourism promotion and ensure dispersal of tourism to the remotest areas to the State. The Scheme of 'Paying Guest House' will be covered under the tiny sector of the Rules for the grant of Incentives to Tourism Industry in Himachal Pradesh 1993 which come in to force w. e. f. 1-8-1993.

It is a low cost Scheme shifting the focus from already saturated destinations such as Shimla, Manali, Kullu, Dalhousie, Dharamshala etc., in terms of Hotel accommodation by providing accommodation in alternate locations such as Tea Gardens, Farm Houses, Orchards, Religious Places and other rural places of natural scenic beauty. Thus the congestion in the towns would be reduced and there by pressures on already over taxed local civic resources would be minimised to some extent. It would be co-friendly enabling the tourists/visitors to live close to nature and enjoy the Himalayan country-side which is the strength of Himachal Pradesh.

The Scheme would provide within a short span of time i. e. within 1-2 years, additional rooms/beds with a low capital investment throughout the State. For this purpose the existing accommodation in the houses located in A and B categories of blocks of the State as envisaged in the Incentive Rules, 1993, is required to have certain facilities like attached bathroom/toilets, extra rooms to be constructed with the existing house with aforesaid facilities and furnishing.

2. *Short title and commencement :*

- (i) The Scheme shall be called the Himachal Pradesh Paying Guest House Scheme, 1995.
- (ii) This Scheme shall come into force from the date of notification.

3. *Definition :*

- (i) *Paying Guest House.*—Any private house located in A and B block areas of the State in good condition and easily accessible in the country-side i. e. within the Farm House, Orchards, Tea-Gardens, Religious Places etc., will primarily qualify under the Scheme. The house shall fulfil the minimum requirement of having two or more rooms accommodation subject to a maximum of nine standard size rooms to cover under the Scheme with attached toilet facility which will be made available to the tourist as Paying Guest House accommodation. The Promoters are at liberty to submit fresh proposals for approval for setting up new Paying Guest Houses in the country-side under the Tiny Tourism Sector of the Incentive Rules, 1993.
- (ii) *Accommodation.*—Accommodation under the Scheme would mean the room accommodation of standard sizes with attached toilets facility ready for letting out to the tourists/quests as prescribed under the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 and the Rules made thereunder as amended from time to time by the State Government. Such accommodation should have regular flow of water and electricity connection. The standard size for double and single bed room accommodation is 120 sq. ft. & 100 sq. ft. respectively and 30 sq. ft. for bathroom/toilet.
- (iii) *Tiny Tourism Units.*—Tiny Tourism units are those units which have a fixed capital investment of Rs. 10 lakhs or less.
- (iv) *Categorisation of areas.*—The entire state has been classified into 'A', 'B', and 'C' categories. The classification has been done with a view to have balanced development of tourism industry in different parts of the State as envisaged in the Incentive Rules, 1993. ANNEXURE-I.

4. *Eligibility :*

- (a) All the new approved tourism units i. e., the tourism units which are approved after the notification of this scheme and under the provisions of this scheme shall be eligible to claim benefit as envisaged hereunder.
- (b) As the incentives under these rules are provided under the discretionary powers of the State Government, hence do not create any claim against Himachal Pradesh Government enforceable in any Court of law.
- (c) Only those units will be eligible to avail of these incentives which follow the instructions/guidelines issued by the Directorate of Tourism regarding architectural designs for the outfacade of buildings to be constructed.

5. *Operation of the Scheme :*

- (i) The Scheme shall be operative in whole of the State but the incentives under tiny sector shall be available in the countryside locations of such houses in A and B category areas of the State only.

- (ii) Any proprietor/owner of the private house located in A and B category of blocks in the State shall apply in the prescribed proforma (Annexure-II) to the Divisional Tourism Development Officer of the Department of Tourism, Himachal Pradesh under whose jurisdiction the area falls for approval and providing financial aid under the Scheme. A Committee consisting of Divisional Tourism Development Officer or any other officer of the Department of Tourism Himachal Pradesh, Sub Divisional Officer (Civil) of the area and leading Hotelier/Travel Agent/Tour operator of the area will inspect the premises being offered and in the event of its being found suitable. The Divisional Tourism Development Officer will approve the project and will further recommend the same to the State Financial Corporation or the Scheduled Banks for providing financial aid by way of loan to the owner concerned.

#### 6. Incentives and its Eligibility :

##### (a) For projects converting the existing accommodation :

- (i) The promoter of existing accommodation in the houses located in A and B categories of blocks of the State providing certain facilities like bathroom/toilets, extra rooms to be constructed with the existing house. The subsidy shall be admissible only against the additions/alterations made.
- (ii) The proprietor of such accommodation shall be eligible for 3% interest subsidy on loan taken from the State Financial Corporation or the banks besides 25% subsidy on fixed capital investment subject to a maximum of rupees one lakh under the Incentive Rules, 1993.

- (b) For construction of new accommodation under the Paying Guest House Scheme.— For construction of new accommodation under the Paying Guest House Scheme in the Tiny Sector of the Incentive Rules, 1993, the proprietor of the said accommodation in A and B categories of blocks in the State shall have to follow the instructions/guidelines as described under Rule 4 (a) and (c) above. The Proprietor of the said accommodation in A and B categories of blocks in the State shall be eligible for 3% interest subsidy and 25% subsidy on fixed capital investment subject to a maximum of Rs. one lakh.

#### 7. Procedural formalities required at the Project as well as registration stage.

As per Annexure-III attached to these rules.

#### 8. Responsibility of the House owners under the Scheme :

- (i) Every Paying Guest House accommodation shall be governed by the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 or the relevant act governing the registration of Hotels and the rules made thereunder as amended from time to time by the State Government and its adherence shall be binding on the owner of the accommodation.
- (ii) The owner of the Paying Guest House accommodation shall at all times maintain the minimum standard of cleanliness, sanitation, quality food etc.

By order,

RENU SAHNI BHAR,  
Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE-I

CATEGORISATION OF AREAS

- 'C' Kullu, Manali, Shimla and Kasauli Towns and Dhalli NAC Area.
- 'B' Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Hamirpur, Kangra, Dharamshala, Palampur, Mandi, Nahan, Paounta Sahib, Parwanoo, Solan and Una Towns and Kaumptati Block, Dharampur Block and Rest of Kullu and Manali Block.
- 'A' Rest of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-II

APPLICATION FORM UNDER THE PAYING GUEST HOUSE SCHEME, 1994.

1. Name and address of the applicant (Entrepreneur).
2. Father's name
3. Name of the proposed project with location (state whether adding new rooms to the existing house with toilet facility or totally a new project).
4. Area of the existing house/land for the project (attach Revenue papers).
5. Land measuring.....  
situated in Khas a No.....  
In Mohal.....  
Vill.....Patwar Circle.....  
Teh.....Distt.....  
(H. P.).
6. Blue prints/site plan of the proposed accommodation in the existing house/new proposed project with abstract of cost duly signed by some Architect, A.E.
7. NOC from the Town and Country Planning Department of the area.
8. NOC from the Panchayat with Certificate that the case does not fall under the TCP Department is within the Jurisdiction of Panchayat only.

9. Project profile.
10. Affidavit reg. clear and undisputable title of the promoter to the House/land and to run the PGH for atleast 10 years from the date of Registration and commercial functioning.
11. Affidavit in case of cosharer of the House/land proposed for the P. G. H.
12. Name of the Financial Institution from where the financial aid is to be taken for the proposed project of Paying Guest House.

Dated.....

Signature of applicant.

### ANNEXURE-III

#### LIST OF DOCUMENTS REQUIRED AT PROJECT STAGE AND REGISTRATION STAGE IN RESPECT OF PAYING GUEST HOUSE SCHEME, 1994

Project approval stage 1	Remarks 2
1. Title papers from the Rev. Department regarding Ownership of existing house/land (Jamabandi and Tatima from Patwari).	
2. Feasibility Report	The project under tiny Tourism unit are recommended by the Director Tourism, Himachal Pradesh to Financial Institution/ Bank for financial aid.
3. Blue Print/Estimated cost from A. E. and NOC/Clearance from TCP Department if falls in its extended jurisdiction or certificate from Patwari and Panchayat Pradhan that the area does not fall with in the jurisdiction of TCP Department.	
4. Affidavit to run the said house atleast for 10 years.	
<b>Registration stage :</b>	
1. Application for registration on prescribed Form.	
2. Completion Certificate	
3. Affidavit under section 6 of the H. P. R. O. H. and T. A. Act, 1970.	

1

2

4. Inspection report reg. room sizes and facilities by the D. T. D. O. or any other Officer of the Department.
5. Rev. Papers
6. Plan
7. Registration fee of Rs. 50/- Payable to the Director Tourism, Himachal Pradesh.

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### OFFICE ORDER

*Shimla-1, the 6th March, 1995*

No. HIM/TP-Delegation of Powers/95-Volume-II-15431-93.—In exercise of the powers vested in the undersigned *vide* sub-section (2) of section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), I hereby delegate powers as exerciseable under section 15 (A), 16, 33, 39, 79 and 81 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Parwanoo, Kasauli, Baldi Barotiwala and Nilgiri Planning Areas to Executive Engineer, Development Control Division, Parwanoo, District Solan, H. P. in supersession of this office order No. HIM/TP-Delegation of Powers/93-Volume-I-13457-13557 Saim'a dated 12-1-95 with immediate effect.

Sd/-  
Director.

अधिसूचना

शिमला-2, 8 मार्च, 1995

संख्या आवास टी 0 सी 0 पी 0-1-123/92-I—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के खजियार गांव, हदबस्त नं 0 31 को लोकहित में विशेष योजना क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक और समीचीन है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त क्षेत्र को विशेष धत्व के रूप में घोषित करते हैं जो कि खजियार विशेष योजना क्षेत्र के रूप में जाना जायगा और उपरोक्त अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (2) के प्रयोग के लिए इसकी सीमाएं खजियार गांव, हदबस्त नं 0 31 तक परिभाषित करते हैं।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-1-123/92-I, dated 8-3-1995 as required under Article 343(3) of the Constitution of India].

Shimla-171 002, the 8th March, 1995

**No. TCP-1-123/92-I.**—Whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest that Village Khajjiar, Hadbast No. 31, District Chamba (H.P.) may be developed as a special area.

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 66 of the H.P. Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the above areas as a special area known as "Khajjiar Special Planning Area" and to define its limits as Khajjiar Village, Hadbast No. 31 for the purpose of sub-section (2) of section 66 of the Act *ibid*.

By order,

P. S. NEGI,  
F. C.-cum-Secretary.

### OFFICE ORDER

Shimla-1, the 23rd March, 1995

**No. HIM/TP-Delegation of Powers/95-Volume-II.**—In exercise of the powers vested in the undersigned *vide* sub-section (2) of Section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) I hereby delegate powers as exercisable under section 15-A, 38, 39, 79 and 81 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Dalhousie Planning Area to the Assistant Town planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Chamba, District Chamba H. P. with immediate effect.

Sd/-  
Director.

### TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

#### CORRIGENDUM

Shimla-171 002, the 16th March, 1995

**No. STV (TE) A (3) 8/87**—Please read pay scale of "Rs. 1500-50-2000-60-2050-70-2550-75-2700" instead of Rs. 1500-30-1550-40-2000-50-2500-60-2640 in column No. 4 of Annexure-A of this Department's Notification of even number dated 10th June, 1994.

By order,

Sd/-  
Commissioner-cum-Secretary.



हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शुद्धि पत्र

शिमला-4, 23 फरवरी, 1995

संख्या 6-24/86-वि० स०.—इस कार्यालय की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 1995 की पांचवीं एवं छठी पंक्तियों के स्थान पर निम्न शब्द पढ़ें जायें:—

“हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सचिव के पद पर नितान्त तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है।”

आदेश द्वारा,

अध्यक्ष,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।